अमर उजाला 19/1/013

पांच लाख विज्ञान शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

जीबीटीयू की वर्कशॉप के दौरान विशेषज्ञों ने गिनाई प्राथमिकताएं

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) बेसिक साइंस में छात्रों की घटती रुचि को लेकर चिंतित है। यह प्रवृत्ति रोकने के लिए विज्ञान शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए डीएसटी ने देश भर में विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें पांच साल में पांच लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के दायरे में स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षक आएंगे।

जीबीटीयू की वर्कशाप में हिस्सा लेने आए डीएसटी के एडवाइजर ए. मुखोपाध्याय ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बेस्ट (बिल्डिंग एजुकेटर फॉर साइंस टीचिंग) स्कीम शुरू की है। इसके अंतर्गत विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाएगा। हर साल एक लाख शिक्षक इस योजना का हिस्सा होंगे। फिलहाल केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण से इसकी शुरूआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम 1000 डॉक्टोरल एवं 250 पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप विदेशों में अध्ययन के लिए शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत डीएसटी द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में शोध एवं अध्ययन के लिए यहां के शोधार्थियों को अध्ययन के लिए विदेश भेजा जाएगा। विज्ञान को बढ़ावा देने की योजनाओं में यूपी की भागीदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहां के छात्रों की भागीदारी छात्रवृत्ति में काफी अच्छी है। इंस्पायर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के और खासकर यूपी बोर्ड के 5000 छात्र फैलोशिप के लिए चुने गए हैं। यह देश के किसी भी राज्य में इस योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या है। इंस्पायर के अंतर्गत चयनित छात्रों को बेसिक साइंस के विषयों में स्नातक एवं परास्नातक करने के लिए हर वर्ष डीएसटी 80 हजार रुपये की स्कालरशिप देगा। यूपी से लगभग 8000 प्रपोजल आए थे। उनमें से 5000 स्वीकार कर लिए गए।

- *इंस्पायर फैलोशिप पाने वाले सबसे अधिक छात्र यूपी के*

कॅरिअर को दिशा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उन महिला वैज्ञानिकों के कॅरिअर को दिशा देने का मन बनाया है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपना शोध कार्य आगे नहीं बढ़ा सकी। डीएसटी के एडवाइजर डॉ. जीजे समाथानम ने बताया कि डीएसटी ने दिशा योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत जो महिला वैज्ञानिक घरेलू कारणों या पति के स्थानांतरण आदि समस्याओं के चलते विज्ञान एवं शोध से कट गई है। उनको इनसे जोड़ा जाएगा। इसके लिए संविदा आधारित तीन से पांच वर्ष तक के कार्य के लिए पद सृजित किए जाएंगे। महिलाओं के शोध प्रस्ताव पर परीक्षण के पश्चात उन्हें चयनित विषय पर कार्य करने के लिए डीएसटी अनुदान देगी।

दो दिनी कार्यशाला के दूसरे दिन शक्रवार को जीबीटीयू के कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने अपनी जिज्ञासाएं शांत की।

जीबीटीयू में खुलेगा रेडिएशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

लखनऊ। गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय में रेडिएशन प्रोसेसिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की तैयारी है। कुलपति प्रो. आरके खांडल के प्रस्ताव पर बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज (बीआरएनएस) ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बीआरएनएस के अधिकारियों ने जीबीटीयू से इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस कड़ी में बीआरएनएस ने 16 फरवरी को अंबालिका इंस्टीट्यूट में रेडिएशन पर एक वर्कशाप की भी मंजूरी दे दी है। जीबीटीयू द्वारा संबद्ध कॉलेजों के लिए कैपिसिटी बिल्डिंग पर आयोजित दो दिवसीय वर्कशाप का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान प्रेजेंटेशन सेशन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बीआरएनएस के सलाहकार डॉ. ललित वार्ष्णेय ने योजनाओं के साथ ही रेडिएशन सेंटर के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि यूपी में कृषि एवं बॉयोमेडिकल आदि की संभावनाओं को देखते हुए रेडिएशन प्रोसेसिंग की तकनीक काफी फायदेमंद हो सकती है। प्रेजेंटेशन के दौरान ही कुलपति प्रो. आरके खांडल ने जीबीटीयू में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की मांग की, जिस पर वार्ष्णेय ने सैद्धांतिक तौर पर सहमति प्रदान कर दी। सेंटर खुलने से न केवल रेडिएशन तकनीक के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अन्य शोध के लिए भी इसके जरिए जीबीटीयू कॉलेज अनुदान के लिए प्रस्ताव भेज सकेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार डॉ. जीजे समाथानम एवं डॉ. ए मुखोपाध्याय ने शोध एवं संसाधन के लिए अनुदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस पर निराशा जाहिर की कि यूपी के कॉलेज प्रस्ताव भेजने में सबसे फिसड्डी हैं। हर वर्ष डीएसटी को मिलने वाले प्रस्तावों में सबसे कम संख्या यूपी की होती है। यहां तक कि चयन के बाद प्रेजेंटेशन तक के लिए कॉलेज नहीं आते हैं। इस पर कुलपति प्रो. आरके खांडल ने जीबीटीयू के लिए जहां विशेष पैकेज की मांग की वहीं यह भी आश्वासन दिया कि जीबीटीयू अपने हर कॉलेज का उसकी क्षमता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कराएगा और उसकी तकनीकी औपचारिकताओं को भी स्वयं देखेगा। जिससे छात्रों के लिए बेहतर संसाधन एवं शोध सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

- *क्षमता विकास पर वर्कशाप का समापन*
- *कॉलेजों के ग्रांट के प्रस्ताव खुद तैयार कराएगा जीबीटीयू*
- *प्रपोजल भेजने में यूपी के कॉलेज सबसे फिसड्डी*

अमर उजाला 19/1/013